बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-14
05/01/2020

मुख्यमंत्री ने सुपौल में जल–जीवन–हरियाली से संबंधित प्रमण्डलस्तरीय समीक्षा बैठक की

पटना, 05 जनवरी 2020 :– जल–जीवन–हरियाली यात्रा के क्रम में सुपौल समाहरणालय के टी0सी0पी0 भवन में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल–जीवन–हरियाली अभियान से संबंधित कोसी प्रमंडल अंतर्गत सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले की संयुक्त समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में सार्वजनिक कुंओं, चापाकल, आहर, पइन का जीर्णोद्धार, नलकूपों, कुओं एवं चापाकल के किनारे सोख्ता निर्माण, जल संरक्षण संरचना, छोटी–छोटी नदियों, नालों, पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों पर छत वर्षा जल संचयन, पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियाँ, राज्य में बची सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जर्जर तारों का बदलाव, पॉवर सब स्टेशन के निर्माण से संबंधित जानकारी भी दी गई। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने–अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अपनी बातें रखीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिकायतों के शीघ्र निष्पादन के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अतिक्रमण मुक्त अभियान के संदर्भ में निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमणमुक्त अभियान से जो अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीब तबके के बेघर लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें वैकल्पिक स्थान पर ले जाने के लिए पहले जगह का चयन कर लें। उन्होंने कहा कि कोशी की धार हमेशा बदलती रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग को पुरानी नदियों एवं उप–नदियों के जीर्णोद्धार पर विशेष बल देना होगा। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों को भी इस पर सतत् निगरानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र में जलस्रोत सृजन की काफी संभावना है, इसका अध्ययन ठीक ढंग से करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिये ताकि भूजल स्तर कायम रहे।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों से 19 जनवरी 2020 को जल–जीवन–हरियाली अभियान एवं नशामुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही मानव श्रृंखला में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित करने की भी बात कही।

बैठक में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति मोहम्मद हारून रसीद, ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विधि एवं लघु जल संसाधन मंत्री श्री नरेन्द्र नारायण यादव, सांसद श्री दिलेश्वर कामत, सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव, विधायक श्री

नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू, विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, संबंधित विभागों के एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री के0 सेंथिल कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में शामिल होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने सुपौल डेयरी का निरीक्षण भी किया।

******